



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार 19 अक्तूबर, 2001/27 अश्विन, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग  
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अक्तूबर, 2001

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-14/2001-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-10-2001 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधायी राज (संशोधन) विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक संख्यांक 14) को वर्ष 2001 के अधिनियम संख्यांक

22 के रूप में अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

रामेश्वर शर्मा,  
सचिव (विधि)।

2001 का अधिनियम संख्यांक 22.

## हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिनियम) विधेयक, 2001

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2001 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8 में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— धारा 8 का संशोधन।

“परन्तु यह और कि ग्राम सभा क्षेत्र के भाग या पूर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाला पंचायत समिति का सदस्य, सम्बद्ध ग्राम पंचायत(तों) का भी सदस्य होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

धारा 11 का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) ग्राम पंचायत, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी।”;

और

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम पंचायत को, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट उन मामलों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने और निष्पादन का कार्य सौंप सकेगी, तथा ग्राम पंचायत उन कृत्यों का पालन भी करेगी।”।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, धारा 23 का अर्थात् :— प्रतिस्थापन।

“23. स्थाई समितियों का गठन और कृत्य.—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, निर्वाचन द्वारा इसके सदस्यों में से निम्नलिखित स्थाई समितियां गठित करेगी :—

(i) प्रधान के नेतृत्व में, ग्रामीण सड़कों और सार्वजनिक भवनों से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, लोक निर्माण समिति, तथा उप-प्रधान भी इस समिति का सदस्य होगा ;

- (ii) प्रधान के नेतृत्व में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा, महिलाओं, बालकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति ;
- (iii) प्रधान के नेतृत्व में, शिक्षा से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, ग्राम शिक्षा समिति ;
- (iv) प्रधान के नेतृत्व में, वनरोपण, भूमि संरक्षण, दावानल निवारण से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, वन समिति ;
- (v) उप-प्रधान के नेतृत्व में, कृषि/बागवानी उत्पादन, पशुपालन से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, कृषि उत्पादन समिति ;
- (vi) उप-प्रधान के नेतृत्व में, सिंचाई और जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य समिति ; और
- (vii) उप-प्रधान के नेतृत्व में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता समिति ।

(2) प्रत्येक समिति में ग्राम पंचायत से, यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान सहित, दो से कम और तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

परन्तु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति तथा वन समिति में, सहयोजित सदस्यों को मिलाकर कम से कम तीन महिला सदस्य होंगे :

परन्तु यह और कि यदि उप-प्रधान, ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य करता है तो उप-धारा (1) के खण्ड (V), (vi) और (vii) में वर्णित स्थाई समिति के सदस्य, अपने में से इसके अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ।

- (3) प्रत्येक समिति, कृषक क्लब, महिला मण्डल, युवक मण्डल, सहकारी सोसाइटी और सम्बद्ध विभागों के सदस्यों को ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, सहयोजित करेगी । सहयोजित सदस्यों के अधिकार और दायित्व ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं :

परन्तु प्रत्येक स्थाई समिति, ग्राम सभा से दो सदस्यों से अनधिक भी, जिन्हें उस विषय, जिसके लिए उक्त समिति गठित की गई है, की जानकारी हो, सहयोजित करेगी :

परन्तु यह और कि एक ही व्यक्ति, दो से अधिक स्थाई समितियों के लिए सहयोजित नहीं हो सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक समिति में सहयोजित सदस्यों सहित, पांच से कम नहीं और 20 से अधिक सदस्य होंगे ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम शिक्षा समिति, वही होगी जैसी हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा नियम, 2000 के अधीन, प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित की गई है।

(5) स्थाई समितियां उप-धारा (1) के अधीन ऐसे कृत्यों का पालन करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 78 की उप-धारा (1) में खण्ड (घ) में, परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— धारा 78  
का संशोधन।

“(ङ) वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला परिषद् का सदस्य, जिसमें पंचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 118 में, उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तु के पश्चात् जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— धारा 118  
का संशोधन।

“परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निदेशक, यदि आवश्यक समझे, निजी अधिकारियों/व्यक्तियों को भी, जो संपरीक्षा में विशेषज्ञ हों, संदाय के आधार पर संपरीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।”

7. मूल अधिनियम की धारा 161 में,— धारा 161  
का संशोधन।

(क) खण्ड (ii) में, “जिला परिषद्” शब्दों के पश्चात् और “के मामले में” शब्दों से पूर्व, “के सदस्यों” शब्द जोड़े जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में, आयुक्त द्वारा।”।

8. मूल अधिनियम की धारा 174 की उप-धारा (1) में,— धारा 174  
का संशोधन।

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) सभी या किसी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित करने; या” ; और

(ख) ऐसे प्रतिस्थापित किए गए खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सभी या किसी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध घोषित करने और याची या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्मक् रूप से निर्वाचित किए जाने, का आदेश करेगा।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 175 में,— धारा 175  
का संशोधन।

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार।” ;

(ख) उप-धारा (1) में, "निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अपास्त कर देगा" शब्दों के स्थान पर, "निर्वाचित व्यक्तियों के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देगा" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) धारा 175-क के उपबन्धों के अधीन, जब उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा चुका हो, तब इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, नया निर्वाचन कराया जाएगा।"

धारा 175-क  
और 175-ख  
का अंतःस्था-  
पन।

10. मूल अधिनियम की धारा 175 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"175-क. निर्वाचित व्यक्ति से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा वे आधार:—यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसने याचिका दाखिल की है निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिए दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है और प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि—

(क) याची को या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमाम्य मतों की बहुसंख्या वास्तव में प्राप्त हुई है, अथवा

(ख) निर्वाचित व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण द्वारा, अभिप्राप्त मतों के अभाव में याची या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमाम्य मतों की बहुसंख्या अभिप्राप्त हुई होती,

तो प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के पश्चात् यह घोषणा करेगा कि, यथास्थिति, याची या ऐसा अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

175-ख. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया:—यदि निर्वाचन याचिका के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में एक मत के जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा, तो—

(क) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई विनिश्चय वहां तक, जहां तक कि उन अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न का अवधारण करता है, उस याचिका के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा; और

(ख) जहां तक कि वह प्रश्न ऐसे विनिश्चय द्वारा अवधारित नहीं हुआ है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उन के बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस किसी के पक्ष में लाट निकल आए उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ था।"

धारा 181  
का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 181 में, विद्यमान खण्डों (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) उप-मण्डल अधिकारी द्वारा पारित आदेश की दशा में, उपायुक्त को, और इस खण्ड के अधीन पारित उसका आदेश अंतिम होगा;

- (ii) उपायुक्त द्वारा पारित मूल आदेश की दशा में, विन्यायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार को; और
- (iii) आयुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में, विन्यायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार को,

अपील कर सकेगा और वह अपील की गुनवाई करेगा तथा 90 दिन के भीतर उसका निपटारा करेगा, और अपील पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।”।

12. मूल अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची-1  
का प्रति-  
स्थापन।

### “अनुसूची-1

[धारा 11 (1) देखें]

ग्राम पंचायत के कृत्य

1. स्वच्छता, सफाई और न्यूसेन्स का निवारण और उसका उपशमन ;
2. सार्वजनिक कुओं, तालाबों और टैंकों तथा परम्परागत पारम्परिक जल के स्रोतों का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण ;
3. ग्राम पथों, खच्चरों के लिए सड़कों और ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और बांधों, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित तथा पोषित न हों, का सन्निर्माण और अनुरक्षण ;
4. सार्वजनिक मार्गों, शौचालयों, नालियों, टैंकों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सन्निर्माण, अनुरक्षण और इनकी सफाई ;
5. भवनों, शौचालयों, मूत्रालयों, नालियों तथा फलन शौचालयों के सन्निर्माण का विनियमन ;
6. कचरा इकट्ठा करना और व्ययन करना तथा कचरा क्षेपण के लिए स्थानों का पृथक रक्षण ;
7. उपयोग न किए जाने वाले कुओं, अस्वच्छ तालाबों, पोखरों, खाइयों तथा गड्ढों को भरना और सीढ़ीदार कुओं (बावडियों) को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना ;
8. ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना ;
9. सार्वजनिक मार्गों या स्थानों और उन स्थलों में, जो निजी सम्पत्ति न हों या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हों या राज्य सरकार के हों, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना ;
10. सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम पंचायत में निहित या उसके नियन्त्रणाधीन ग्राम स्थल, चारागाहों तथा अन्य भूमियों का प्रबन्ध और विकास ;
11. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए से भिन्न, प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण ;
12. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का अनुरक्षण ;
13. वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण ;
14. शवों, पशु-शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन ;
15. लावारिस शवों और पशु शवों का व्ययन ;
16. मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन ;
17. कांजी-हाउस की स्थापना और प्रबन्ध तथा पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना ;
18. बाजारों और मेलों की स्थापना, प्रबन्ध तथा विनियमन ;
19. जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना।”

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 22 of 2001.

## THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2001

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH OCTOBER, 2001)

AN  
ACT*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2001.

Amendment  
of section  
8.

2. In section 8 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after the second proviso, the following shall be added, namely:—

4 of 1994

“Provided further that the member of the Panchayat Samiti, representing a part or whole of the Gram Sabha area shall also be the member of the concerned Gram Panchayat(s) and shall have the right to vote.”

Amendment  
of section  
11.

3. In section 11 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) The Gram Panchayat shall perform the functions specified in Schedule-I.”; and

(b) in sub-section (2), for the words and sign “specified in Schedule-II”, the words and sign “including those matters specified in Schedule-II and the Gram Panchayat shall perform such functions” shall be substituted.

Substitution  
of section  
23.

4. For section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“23. *Constitution and functions of Standing Committees.*—(1) Every Gram Panchayat shall from amongst its members constitute by election, following Standing Committees:—

- (i) Public Works Committee for performing functions relating to rural roads and public buildings to be headed by the Pradhan and the Up-Pradhan shall be the member of this committee;
- (ii) Health and Family Welfare Advisory Committee for performing functions relating to Health and Family Welfare



Department, welfare of women, children, Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be headed by the Pradhan;

- (iii) Village Education Committee for performing functions relating to education to be headed by the Pradhan ;
- (iv) Forest Committee for performing functions relating to afforestation, soil conservation, prevention of forest fire to be headed by the Pradhan ;
- (v) Agriculture Production Committee for performing functions relating to Agriculture/Horticulture production, Animal Husbandry to be headed by the Up-Pradhan ;
- (vi) Irrigation and Public Health Committee for performing functions relating to Irrigation and Public Health to be headed by the Up-Pradhan ;
- (vii) Food, Civil Supply and Consumers Committee to be headed by Up-Pradhan.

(2) Each Committee shall consist of not less than two and not more than three members from Gram Panchayat including the Pradhan or the Up-Pradhan, as the case may be :

Provided that the Health and Family Welfare Advisory Committee and Forest Committee shall have at least three women members including co-opted members :

Provided further that if the Up-Pradhan acts as the Pradhan of the Gram Panchayat, the members of the Standing Committees mentioned in clauses (v), (vi) and (vii) of sub-section (1) shall elect its Chairman from amongst themselves .

(3) Each Committee shall co-opt, in such manner as may be prescribed, members of Farmers Club, Mahila Mandals, Yuvak Mandals, Co-operative Societies and the concerned departments. The rights and liabilities of the co-opted members shall be such as may be prescribed :

Provided that each Standing Committee shall also co-opt not more than two members from Gram Sabha having knowledge of the subject for which the said committee had been constituted :

Provided further that the same person may not be co-opted for more than two Standing Committees :

Provided further that each committee shall consist of not less than five and not more than twenty members including the co-opted members.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the Village Education Committee shall be the same as notified by the Primary Education Department under the Himachal Pradesh Compulsory Primary Education Rules, 2000.

(5) The Standing Committees shall perform such functions under sub-section (1) as are entrusted to them by the Gram Panchayat."

Amendment  
of section  
78.

5. In section 78 of the principal Act, in sub-section (1), after proviso to clause (d), the following shall be added, namely :—

“(e) the member of the Zila Parishad, representing the ward which comprises wholly or partly the Panchayat Samiti area.”.

Amendment  
of section  
118.

6. In section 118 of the principal Act, after sub-section (2), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that the Director may, with the prior approval of the State Government, also authorise private agencies/persons, who are specialised in audit to conduct audit, on payment basis, if considered essential.”.

Amendment  
of section  
161.

7. In section 161 of the principal Act :—

(a) in clause (ii), after the words “in the case of”, the words “members of” shall be added; and

(b) after clause (ii), the following shall be added, namely:—

“(iii) in the case of Chairman and Vice-Chairman of Zila Parishad, by the Commissioner.”.

Amendment  
of section  
174.

8. In section 174 of the principal Act, in sub-section (1), —

(a) for clause (b), the following shall be substituted, namely :—

“(b) declaring the election of all or any of the elected persons to be void ; or” ; and

(b) after clause (b) so substituted, the following clause (c) shall be added, namely :—

“(c) declaring the election of all or any of the elected persons to be void and the petitioner or any other candidate to have been duly elected.”.

Amendment  
of section  
175.

9. In section 175 of the principal Act,—

(a) for the existing heading, the following shall be substituted, namely:—

“Grounds for declaring elections to be void.”;

(b) in sub-section (1), for the words “set aside the election of the elected person”, the words “declare the election of the elected persons to be void” shall be substituted; and

(c) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Subject to the provisions of section 175-A, when an election of an elected person has been declared to be void under sub-section (1), a fresh election shall be held under the provisions of this Act and the rules made thereunder.”.

10. After section 175 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

Insertion of sections 175-A and 175-B.

**“175-A. Grounds for which a candidate other than the elected person may be declared to have been elected.—**If any person who has lodged a petition has, in addition to calling in question the election of the elected person, claimed a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected and the authorised officer is of opinion,—

- (a) that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of valid votes; or
- (b) that but for the votes obtained by the elected person by corrupt practices, the petitioner or such other candidate would have obtained a majority of the valid votes,

the authorised officer shall after declaring the election of the elected person to be void declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected.

**175-B. Procedure in case of equality of votes.—**If during the trial of an election petition, it appears that there is an equality of votes between any candidates at the election and that the addition of a vote would entitle any of those candidates to be declared elected, then—

- (a) any decision made by the returning officer under the provisions of this Act shall, in so far as it determines the question between those candidates, be effective also for the purposes of the petition; and
- (b) in so far as that question is not determined by such a decision, the authorised officer shall decide between them by lot and proceed as if the one on whom the lot then falls had received an additional vote.”.

11. In section 181 of the principal Act, for the existing clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

Amendment of section 181.

- “(i) in case the order is passed by the Sub-Divisional Officer, to the Deputy Commissioner and his orders passed under this clause shall be final ;
- (ii) in case the original order is passed by the Deputy Commissioner, to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh ; and
- (iii) in case the order is passed by the Commissioner, to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh,

and he shall hear and dispose of the appeal within a period of 90 days whose decision shall be final.”.

Substitution  
of Schedule-  
I.

12. For Schedule-I appended to the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I

[See section 11 (1)]

FUNCTIONS OF GRAM PANCHAYATS

1. sanitation, conservancy and prevention and abatement of nuisance;
2. construction, repair and maintenance of public wells, ponds, tanks and conventional/traditional sources of water;
3. construction and maintenance of village paths, mule roads and rural roads, culverts, bridges and bunds which are not constructed or maintained by the Public Works Departments;
4. construction, maintenance and cleaning of public streets, latrines, drains, tanks, wells and other public places;
5. regulating the construction of buildings, latrines, urinals, drains and water closets;
6. collection and disposal of refuse and earmarking places for dumping of refuse;
7. filling of disused wells, in sanitary ponds, pools, ditches and pits and conversion of step wells into sanitary wells;
8. lighting of village streets and other public places;
9. removing of obstructions and projections in public streets or places and in sites not being private property or which are open to use of public, whether such sites are vested in the Panchayat or belong to the State Government;
10. management of public land and management and development of village site, grazing lands and other lands vested in or under the control of the Gram Panchayat;
11. maintenance of ancient and historical monuments other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance;
12. maintenance of Gram Panchayat property;
13. plantation and preservation of Panchayat Forests;
14. regulating places for disposal of dead bodies, carcasses and other offensive matters;
15. disposal of unclaimed corpses and carcasses;
16. regulation of sale and preservation of meat;
17. establishment and management of cattle ponds and maintenance of records relating to cattle;
18. establishment, management and regulation of markets and fairs; and
19. maintenance of records of births, deaths and marriages.”